



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

“ हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जुलाई, 2003/30 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 21 जुलाई, 2003

संख्या वि० स० लैज०-गवरनमेंट बिल/1-82/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन

विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक-18) जो आज दिनांक 21 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2003 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2003 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) में "दो हजार पांच सौ" तथा "एक हजार दो सौ पच्चास" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "चार हजार" तथा "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में "चार सौ" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे । धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में "पांच हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "आठ हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 4-ख का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4-घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 4-ड जोड़ी जाएगी, अर्थात् :- धारा 4-ड का जोड़ना ।

"4-ड. भूतपूर्व सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम.—ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए, ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाएं, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में तीन लाख रुपए संदत्त किए जाएंगे और यह अग्रिम यथास्थिति, उनकी पेन्शन या पारिवारिक पेन्शन से पांच वर्षों के भीतर वसूल किया जाएगा ।" ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "सात हजार" शब्द रखे जाएंगे । धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- धारा 5-क का प्रतिस्थापन ।

"5-क. प्रत्येक सदस्य, वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्रस्तुत करने पर, उस द्वारा संदत्त विद्युत और जल प्रभारों की, प्रतिमास एक हजार रुपए अधिकतम के अध्वधीन, प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।" ।

धारा 6 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,—

(क) तृतीय और चतुर्थ परन्तुक में, “वायु मार्ग द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या लोक परिवहन द्वारा” शब्द जोड़े जाएंगे ; और

(ख) विद्यमान तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“ परन्तु यह और कि सदस्य, जब सरकारी प्रवास (ऑफिसियल टूर) पर हो, तो वायु मार्ग या रेल या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के दौरान उसकी पत्नी या पति या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, ऐसे उपगत वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा ।” ।

धारा 6—क का

अन्तःस्थापन । किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 6—क क से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा 6—क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“ 6—क. भूतपूर्व सदस्यों को रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा निशुल्क यात्रा (ट्रांजिट) सुविधा.—(1) कोई भी भूतपूर्व सदस्य, अपनी पत्नी या पति या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति सहित भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे में किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा और की गई ऐसी यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर ऐसे उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा:

परन्तु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में की गई ऐसी यात्रा पर इस प्रकार उपगत कुल रकम, द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा पंद्रह हजार किलोमीटर तक की गई यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति और उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस प्रतिपूर्ति के विरुद्ध, किसी वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा यात्रा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सदस्य और उसकी पत्नी या पति या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, भारत में वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा भी यात्रा कर सकेगा और उस दशा में ऐसी यात्रा के टिकट प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा पर उपगत व्यय के बराबर की रकम की प्रतिपूर्ति ऐसे भूतपूर्व सदस्य को की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूर्ति रकम का समायोजन उसकी रेल द्वारा यात्रा करने की हकदारी के विरुद्ध किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल या वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बे द्वारा पंद्रह हजार किलोमीटर की यात्रा के लिए संदेय रेल टैरिफ की रकम से अधिक नहीं होगी ।” ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो कि राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख-सुविधाओं के पुनरीक्षण के लिए लगातार मांग रही है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को भवननिर्माण अग्रिम और रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा निशुल्क यात्रा (ट्रांजिट) की सुविधा दी जाए। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरमद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला.....

तारीख.....

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 9 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग नब्बे लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को, उन शर्तों का उपबन्ध करने के लिए जिन पर कि भूतपूर्व सदस्यों को भवन निर्माण अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या: जी.ए.डी-सी(पी.ए.) 6-2/2001]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) विधेयक, 2003 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरमद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे० एल० गुप्ता,
सूचिव (विधि) ।

शिमला.....

तारीख.....

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follow:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Short title.
(Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2003.

8 of 1971

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the "principal Act"), in sub-section (1), for the words **"two thousand and five hundred"** and **"one thousand two hundred and fifty"**, the words **"four thousand"** and **"five thousand"** shall respectively be substituted. Amendment of section 3.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words **"four hundred"**, the words **"five hundred"** shall be substituted. Amendment of section 4.

4. In section 4-B of the principal Act, for the words **"five thousand and five hundred"**, the words **"eight thousand"** shall be substituted. Amendment of section 4-B.

4-A. After section 4-B of the principal Act, the following new section 4-BB shall be added namely:—

15

"4-BB Office Allowance.- There shall be paid to each Member an office allowance at the rate of **five thousand** rupees per mensem."

5. After section 4-D of the principal Act, the following new section 4-E shall be added, namely:— Addition of section 4-E.

"4-E. **House building advance to ex-members.**—There may be paid to such ex-members, who have not availed of the facility of house building advance as a member, by way of repayable advance of **rupees three lakhs** subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the construction of a house or for the purchase of a built up house and the advance shall be recovered from their pension or family pension, as the case may be, within five years.

Amendment
of
section 5.

6. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), in first proviso, for the words "five thousand", the words "seven thousand" shall be substituted.

Substitution
of
section 5-A. namely,—

7. For section 5-A of the principal Act, the following shall be substituted,

"5-A. Every member shall, on the production of actual payee's receipt, be entitled to the reimbursement of the amount of electricity and water charges bill paid by him subject to a maximum of **one thousand rupees per mensem.**"

Amendment
of
section 6.

8. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1),—

- (a) in the third and fourth provisos, after the words "by air", the words "**or by public transport**" shall be added; and
- (b) after existing third proviso, the following new proviso shall be added, namely :—

"Provided further that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his spouse or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport on production of tickets for such journey performed."

Insertion
of
section 6-A.

9. The existing section 6-A of the principal Act shall be re-numbered as section 6-AA and before section 6-AA as so re-numbered, the following new section 6-A shall be inserted, namely :—

"6-A. **Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking to ex-members.**—(1) An ex-member shall be entitled to travel by second class air conditioned railway coach, at any time, by any railway in India, as per current coaching tariff, issued by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board), alongwith his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed :

Provided that the aggregate amount so incurred on such journey, in any financial year, shall not exceed the amount of railway tariff payable for fifteen thousand kilometers journey performed by second class air conditioned railway coach :

Provided further that an ex-member and his spouse or any other person accompanying him to look after and assist him may travel by any air conditioned railway coach against this reimbursement:

Provided further that journey may also be performed within India by air or by public transport by an ex-member and his spouse or any other person accompanying him to look after and assist him during travel and in that event an amount equivalent to the expenses incurred on such journey shall be reimbursed to such ex-member on production of tickets of such journey and the amount so reimbursed shall be adjusted against his entitlement to travel by rail :

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport in a financial year shall not exceed the amount payable for fifteen thousand kilometers by second class air conditioned railway coach."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as public representatives have to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities. It has also been decided thea the facilities of house bulding advance and free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking be extend to the ex -members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allownces and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to aqchieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The.....July, 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 9 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 90.00 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill empowers the Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly to make rules to provide for the conditions on which the house building advance may be sanctioned to ex-members. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA) D (6)-2/2001-]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES
AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2003.**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)
Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).*

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The July, 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , हिमाचल प्रदेश-171005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।